बरुण मित्रा भा.प्र.से.
Barun Mitra, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

अर्ध सरकारी पत्रांक-15011/35/2021-न्याय (एयू) दिनांकः 10 मई, 2021

मैं आपको न्याय विभाग से संबंधित अप्रैल, 2021 माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा।

1. **उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तिः**

   न्यायमूर्ति श्री नुथलापति वेंकट रमण को दिनांक 06-04-2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 24-04-2021 से उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. **उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तिः**

   दो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों को क्रमशः दिनांक 09-04-2021 और दिनांक 27-04-2021 की अधिसूचनाओं के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था।

3. **उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्तिः**

   एक अपर न्यायाधीश को दिनांक 28-04-2021 की अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, ने दिनांक 31-03-2021 से त्यागपत्र दे दिया है। इसे दिनांक 28-04-2021 को अधिसूचित किया गया था।

5. बुनियादी ढांचा विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम:

स्कीम को आगे जारी रखने के लिए न्यायपालिका अधिकारियों के लिए बुनियादी ढांचा विकास पर केंद्र प्रायोजित स्कीम के संबंध में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक दिनांक 12-04-2021 को आयोजित की गई थी।

6. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:

बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्टों को दो और वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23) के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर दिनांक 12-04-2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया था।

7. ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का फेज-।।:

- विविध यातायात अपराधों के लिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में नए वर्चुअल कोर्टों का उद्घाटन किया गया।
- पिछले निर्णयों और आदेशों को तलाश करने के लिए निर्णय और आदेश सर्च पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। यह पोर्टल केस नंबर, अधिनियम, धारा, न्यायाधीश/पक्षकार का नाम, निर्णय की तारीख आदि जैसे अनेक तलाशी मानदंड पर आधारित निर्णय/आदेशों को तलाश करने में मदद करता है।
- वकालतनामा के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, ई हस्ताक्षर, शपथ की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन भुगतान, विविध आई ए/अर्जी दायर करने, पोर्टफोलियो प्रबंधन और द्विभाषी स्वरूप सहित सशक्त, उन्नत और प्रयोक्ता अनुकूल विशेषताओं के साथ ई फाइलिंग वर्जन 3.0 शुरू किया गया है।

- ईकोर्ट फेज-।।। के लिए कार्रवाई योजना (रोड मैप) तैयार करने के लिए एक प्रारूप विजन दस्तावेज भारत के उच्चतम न्यायालय की ई- समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ उप समिति द्वारा तैयार किया गया है। इस दस्तावेज को अब सभी हित धारकों और इच्छुक पक्षकारों से टिप्पणी मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की वेबसाइट अब हिंदी, उड़िया, तमिल, मराठी और खासी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इसके अलावा, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए प्रयोक्ता मैनुअल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी और तेलुगू भाषा सहित आठ भाषाओं में जारी किया है और वेबसाइट पर अपलोड किया है।

8. टेली लॉ:

66,536 व्यक्तियों को कानूनी सलाह दी गई थी जिसमें 22,784 महिलाएं, 20,445 अनुसूचित जातियों, और 14,939 अनुसूचित जनजातियों, तथा 18,816 अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 247 लाभार्थियों को कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित सलाह भी दी गई थी। 30 अप्रैल, 2021 तक कुल 7,88,816 सलाह दी गई है। 8 राज्यों में 19 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र संचालित किए गए जिनमें 560 वीएलई/ पीएलवी ने हिस्सा लिया। टेली लॉ कार्यक्रम के न्याय चाहने के लिए गरीबों और सीमावर्ती व्यक्तियों की सेवा करने और उन्हें समर्थ करने के 4 वर्ष 20 अप्रैल, 2021 को पूरे हो गए हैं।

9. न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस):

न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल पर 44 नए वकील पंजीकृत हुए हैं। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत कुल 2579 वकीलों ने पंजीकरण किया है। एन ए एल एस ए आर, हैदराबाद के विधि छात्र प्रो बोनो क्लब स्कीम से जुड़े हैं।

10. उत्तर पूर्व और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच:

जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 चयनित कानूनों पर 71 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 6840 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 1675 व्यक्तियों को कोविड-19 राहत सेवाएं प्रदान की गईं ।

11. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):

- माह के दौरान 22 राज्यों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 4.58 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया गया। इसके अलावा, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें 193 मामलों का निपटान किया गया।

- अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं और अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए 5 और 6 अप्रैल, 2021 को कानूनी जागरूकता कैंप आयोजित किया।

12. एसीसी के निर्देशों का अननुपालन

शून्य

भवदीय,
हस्ताक्षर/
(बरुण मित्रा)

श्री राजीव गौबा
मंत्रिमंडल सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि: माननीय विधि और न्याय मंत्री के निजी सचिव, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(बरुण मित्रा)